वैश्विक कारकों पर निवेशकों की नजर

संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 82,626 .76 अंक पर बंद हुआ

मुंबई, 15 फरवरी.आईटी कंपनियों पर दबाव से घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह गिरावट देखी गयी और अब आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर वैश्विक कारकों पर ज्यादा रहेगी. घरेलू स्तर पर अगले सप्ताह आयात-निर्यात के आंकड़े जारी होने हैं. इससे बाजार में निवेश धारणा प्रभावित हो सकती है. निवेशक वैश्विक कारकों से संकेत लेकर अपनी रणनीति तय कर सकते हैं.

बीते सप्ताह आईटी कंपनियों में बड़ी गिरावट देखी गयी. इसका प्रमुख कारण एक अमेरिकी कंपनी द्वारा एआई समर्थित एक ऐसे टूल के विकास की खबर है जिससे भारतीय आईटी कंपनियों को मिलने वाले ऑर्डर के प्रभावित होने की आशंका है. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 953.64 अंक (1.14 प्रतिशत) की साप्ताहिक गिरावट में शुक्रवार को 82,626.76 अंक पर बंद हुआ. इसमें पहले दो दिन तेजी और बाद के तीन दिन गिरावट रही. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक भी 222.60 अंक यानी 0.87 फीसदी उतरकर सप्ताहांत पर 25,471.10 अंक पर रहा.

> सेंसेक्स में सबसे ज्यादा साप्ताहिक नुकसान उठाने वाली चारों कंपनियां आईटी क्षेत्र की रहीं. इंफोसिस का शेयर 9.12 प्रतिशत, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 8.70 प्रतिशत, टीसीएस का 8.48 प्रतिशत और टेक महिंद्रा का 5.18 प्रतिशत गिर गया. एफएमसीजी कंपनियों में हिंदुस्तान यूनीलिवर का शेयर 4.89 फीसदी और आईटीसी का 3.82 फीसदी गिर गया जबकि ट्रेंट में 3.22 प्रतिशत की तेजी रही. बैंकिंग एवं वित्तीय कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक का शेयर सेंसेक्स में सबसे ज्यादा 12.42 प्रतिशत उछला. बजाज फाइनेंस में 4.32 प्रतिशत, आईसीआईसीआई बैंक में 0.55 प्रतिशत और बजाज फिनसर्व में 0.01 प्रतिशत की तेजी रही.

यूपी और दिल्ली में उज्ज्वला लाभार्थियों को तोहफा

नई दिल्ली/लखनऊ, 15 फरवरी. होली से पहले लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पात्र लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश में करीब 1.86 करोड़ महिला लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा, जबकि दिल्ली में वैध राशन कार्ड धारकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि ट्रांसफर की जाएगी. त्योहारी सीजन में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच यह कदम परिवारों के बजट को राहत देने वाला माना जा रहा है. राज्य सरकारों ने इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया है, जिससे त्योहार के दौरान रसोई का खर्च कम होगा और जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

कार्बन कटौती में ऐतिहासिक जिम्मेदारी जरूरी

सीतारमण ने विकसित देशों से संतुलित दृष्टिकोण अपनाने को कहा

जलवायु सुरक्षा पर आयोजित एक परिचर्चा में वित्त मंत्री ने यह बात कही

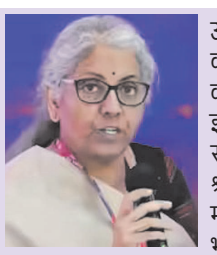

म्युनिख, 15 फरवरी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जर्मनी के म्युनिख में शनिवार को एक परिचर्चा में कार्बन उत्सर्जन पर विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग जिम्मेदार तय करने की मांग करते हुए कहा कि जिन देशों ने पहले कम उत्सर्जन किया है उन्हें ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देशों के बराबर कीमत चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

जर्मनी की यात्रा पर आयीं श्रीमती सीतारमण ने धरती के बढ़ते तापमान के बीच जलवायु सुरक्षा पर आयोजित एक परिचर्चा में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि जिन देशों का उत्सर्जन में कम योगदान रहा है उन्हें भी बराबर कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाये. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपाय में भी सबका योगदान अलग-अलग तय करना होगा. उन्होंने कहा कि भारत ने इन उपायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ायी है. छह साल पहले इस मद में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.7 प्रतिशत खर्च किया जाता था, आज यह आंकड़ा बढ़कर 5.6 प्रतिशत पर पहुंच गया है. भारत ने बाहर से वित्तीय मदद या प्रौद्योगिकी का इंतजार किये बिना इसमें निवेश किया है. वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा पर निवेश करता रहेगा और उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है. वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी कार्बन उत्सर्जन कम करने की रणनीतियों पर निवेश किया गया है ताकि पूरे देश में उन्हें लागू किया जा सके.

> उन्होंने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में से दो-तिहाई को लक्षित समय से पहले हासिल कर लिया है. इससे पहले म्यूनिख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थानीय भारतीय महावाणिज्य दूत शत्रु सिन्हा ने श्रीमती सीतारमण का स्वागत किया. यहां उनका म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और कई परिचर्चाओं में भाग लेने का कार्यक्रम है. वह विभिन्न देशों के मंत्रियों और बहुस्तरीय संगठनों के प्रमुखों से भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगी.

चावल, गेहूं में साप्ताहिक गिरावट

चीनी, खाद्य तेल मजबूत, दालों में घटबढ़

नई दिल्ली, 15 फरवरी. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव घट गये. चावल के साथ गेहूं में भी नरमी रही. चीनी और खाद्य तेलों के दाम बढ़ गये जबकि दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा.

सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 69 रुपये घटकर सप्ताहांत पर 3,753 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं सात रुपये सस्ता हुआ और सप्ताहांत पर 2,856 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका. आटा चार रुपये चढ़कर 3,341 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. बीते सप्ताह खाद्य तेलों में तेजी रही. मूंगफली तेल की औसत कीमत 319 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. सूरजमुखी तेल का भाव 256 रुपये और पाम ऑयल का 222 रुपये बढ़ा. सोया तेल 105 रुपये और सरसों तेल 78 रुपये महंगा हुआ.

सीनियर सिटीजंस स्कीम में 8 .2% ब्याज

30 लाख निवेश पर तिमाही रु .61,500 तक आय

नई दिल्ली, 15 फरवरी. सरकारी योजना में फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जो अन्य पारंपरिक बचत योजनाओं की तुलना में आकर्षक माना जाता है. खास बात यह है कि इस स्कीम में ब्याज तिमाही आधार पर सीधे खाते में जमा होता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को नियमित कैश फ्लो मिलता रहता है.

यदि कोई निवेशक अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे सालाना 2,46,000 रुपए तक ब्याज मिल सकता है. यानी हर तीन महीने में 61,500 रुपए और औसतन करीब 20,500 रुपए प्रतिमाह की आय सुनिश्चित की जा सकती है. सुरक्षित रिटर्न, सरकारी गारंटी और टैक्स लाभ जैसी सुविधाओं के कारण यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के बीच काफी लोकप्रिय है. पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए बनाई गई है.

हालांकि 55 से 60 वर्ष के वे व्यक्ति जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, और 50 से 60 वर्ष के बीच के रिटायर्ड रक्षा कर्मी भी निर्धारित शर्तों के तहत इसमें निवेश कर सकते हैं. इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए से खाता खोला जा सकता है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख रुपए है. वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे सालाना 2,46,000 रुपए ब्याज मिलेगा.

वरिष्ठ नागरिकों को यह योजना आर्थिक स्थिरता देगी

आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेशक 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. हालांकि ब्याज आय कर योग्य होती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि निवेशक तिमाही ब्याज नहीं निकालता, तो उस पर अतिरिक्त ब्याज का लाभ नहीं मिलता. इसलिए इसे नियमित आय योजना के रूप में समझना ज्यादा उचित है. सुरक्षा, निश्चित रिटर्न और सरकारी भरोसे के कारण यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता का मजबूत साधन बन सकती है.

छह कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 3,00,706 करोड़ घटा

मुंबई, 15 फरवरी.आईटी कंपनियों पर दबाव से घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह गिरावट देखी गयी और अब आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर वैश्विक कारकों पर ज्यादा रहेगी. घरेलू स्तर पर अगले सप्ताह आयात-निर्यात के आंकड़े जारी होने हैं. इससे बाजार में निवेश धारणा प्रभावित हो सकती है. निवेशक वैश्विक कारकों से संकेत लेकर अपनी रणनीति तय कर सकते हैं.

बीते सप्ताह आईटी कंपनियों में बड़ी गिरावट देखी गयी. इसका प्रमुख कारण एक अमेरिकी कंपनी द्वारा एआई समर्थित एक ऐसे टूल के विकास की खबर है जिससे भारतीय आईटी कंपनियों को मिलने वाले ऑर्डर के प्रभावित होने की आशंका है. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 953.64 अंक (1.14 प्रतिशत) की साप्ताहिक गिरावट में शुक्रवार को 82,626.76 अंक पर बंद हुआ. इसमें पहले दो दिन तेजी और बाद के तीन दिन गिरावट रही. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक भी 222.60 अंक यानी 0.87 फीसदी उतरकर सप्ताहांत पर 25,471.10 अंक पर रहा. मझौली कंपनियों के निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक में 0.37 प्रतिशत की गिरावट रही.

> बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 26,414 करोड़ रुपये और निर्माण कंपनी एलएंडटी का 14,471 करोड़ रुपये बढ़ गया. आईसीआईसीआई बैंक के एमकैप में 5,720 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई. बाजार पूंजीकरण के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज 19,21,476 करोड़ रुपये के साथ पहले स्थान पर रही. एचडीएफसी बैंक 13,93,622 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और भारती एयरटेल 11,43,044 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रही.

टाटा ग्रुप के दो शेयरों में घटी रिटेल हिस्सेदारी

टाटा पावर और टाटा स्टील में कम हुआ निवेश

मुंबई, 15 फरवरी. दिसंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग पैटर्न रिपोर्ट सामने आने के बाद टाटा ग्रुप की दो प्रमुख कंपनियों में रिटेल निवेशकों की घटती हिस्सेदारी ने बाजार का ध्यान खींचा है.

हालिया आंकड़ों के मुताबिक, टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड में छोटे निवेशकों की संख्या सितंबर तिमाही के मुकाबले कम हुई है. हालांकि शेयरों के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन दीर्घकालिक रिटर्न और सेक्टर की संभावनाओं को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है. सवाल यह है कि क्या यह गिरावट मुनाफावसूली का संकेत है या आगे की रणनीति का हिस्सा? इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड में सितंबर तिमाही तक रिटेल निवेशकों की संख्या 43.36 लाख थी, जो दिसंबर 2025 तिमाही में घटकर 41.78 लाख रह गई. यानी एक तिमाही में करीब 1.58 लाख रिटेल निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी कम की. शुक्रवार को बीएसई पर टाटा पावर का शेयर 1.64% की गिरावट के साथ 374.15 रुपये पर बंद हुआ. पिछले एक वर्ष में इस शेयर ने 7.59% का रिटर्न दिया है.

जियो समेत 10 देशों की 15 टेक कंपनियों ने बनाया 'ट्रस्टेड टेक एलायंस'

म्यूनिख, 15 फरवरी. रिलायंस जियो समेत अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की 15 अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 'ट्रस्टेड टेक एलायंस' (टीटीए) के गठन की घोषणा की है. जियो ने बताया कि यह गठबंधन संचार सुविधा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तक फैले टेक्नोलॉजी स्टैक के लिए भरोसेमंद और सत्यापित मानक विकसित करने के लिए साथ आये हैं.

एफपीआई ने फरवरी में किया 29,714 करोड़ रुपए का निवेश

मुंबई, 15 फरवरी. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने फरवरी में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 29,714 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है.

शुद्ध निवेश लगायी गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर है. सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने फरवरी में इक्विटी में 19,675 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया. वहीं, हाइब्रिड उपकरणों में उन्होंने 1,078 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है. इस अवधि में उन्होंने शुद्ध रूप से 10,930 करोड़ रुपये लगाये. म्यूचुअल फंड में उनका शुद्ध निवेश 188 करोड़ रुपये रहा. एफपीआई दो महीने बाद भारतीय पूंजी बाजार में लिवाल दिख रहे हैं. इससे पहले, जनवरी में उन्होंने 29,071 करोड़ रुपये और पिछले साल दिसंबर में 38,721 करोड़ रुपये निकाले थे.

समाचार विशेष

भाजपा-अकाली गठजोड़ की अटकलें तेज

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के पैदल मार्च से मिले संकेत

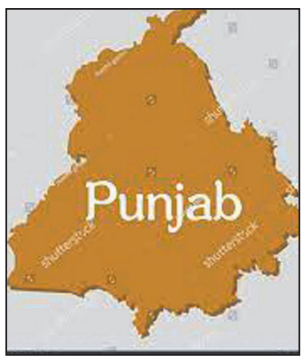

चण्डीगढ़. राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया चार दिन के पंजाब दौरे पर हैं. वे आमजन खासकर युवाओं के साथ बॉर्डर से सटे जिलों में नशा विरोधी जागरूकता मार्च निकाल रहे हैं. फिरोजपुर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ नशा विरोधी पैदल मार्च में सुखबीर बादल और अश्वनी शर्मा की मौजूदगी ने भाजपा-अकाली गठजोड़ की अटकलों को तेज कर दिया है.

हालांकि यह एक जागरूकता मार्च था मगर राज्यपाल के साथ शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर और भाजपा के कार्यकारी प्रभारी अश्वनी शर्मा का होना, इस बात का इशारा कर रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति करवट ले रही है.

इस पैदल मार्च में डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों की मौजूदगी से भी सियासी गलियारों में हलचल है. राज्यपाल कटारिया आमजन खासकर युवाओं के साथ बॉर्डर से सटे जिलों में नशा विरोधी जागरूकता मार्च निकाल रहे हैं. दौरे के दूसरे दिन फिरोजपुर में राज्यपाल का जागरूकता मार्च पंजाब के मौजूदा सियासी समीकरणों के मद्देनजर ज्यादा चर्चा में रहा. सूबे में शिअद फरवरी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह भाजपा से गठजोड़ करना चाहता है, क्योंकि यह गठजोड़ पहले भी पंजाब में सरकार बना चुका है. इस बात पर पंजाब भाजपा के नेता भी दो धड़ों में बंटे हुए हैं. आला नेताओं का एक धड़ा गठबंधन चाहता है मगर दूसरा नहीं.

अंतिम फैसले में भले समय लग सकता है मगर राज्यपाल के साथ शिअद और भाजपा नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दोनों दलों के बीच सियासी कड़वाहट जैसी स्थिति नहीं है. क्या डेरा ब्यास मुखी भी इस गठजोड़ में कोई भूमिका निभा सकते हैं इस बात की भी सियासी गलियारों में खासी चर्चा है, क्योंकि उनकी नजदीकियां शिअद और भाजपा दोनों दलों के नेताओं से है.

भावी संभावनाओं की समीक्षा

भाजपा हाईकमान भी पंजाब में विरोधी दलों की तैयारियों और उनके मुकाबले भाजपा संगठन की धरातल पर स्थिति व भावी संभावनाओं की समीक्षा और आकलन कर रही है. भाजपा-अकाली गठजोड़ के नफा और नुकसान इन दोनों पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

धौलास की जमीन बनी सियासी अखाड़ा

भाजपा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें

देहरादून. धौलास में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए शेखुल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई जमीन का मामला अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर पूरी तरह राजनीतिक अखाड़े में पहुंच चुका है.

भाजपा प्रकरण में जिस तरह से मोर्चा संभाले है, उससे साफ है कि पार्टी इसे नियम विरुद्ध जमीन बेचने के विवाद तक सीमित न रखकर राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाना चाहती है. भाजपा की लगातार घेराबंदी से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं. भाजपा विधायक व प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात, जमीन आवंटन रद्द करने की मांग व देवभूमि में विधर्मियों की मंशा नहीं चलने देंगे जैसे बयानों से भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि यह मामला उसके लिए प्रदेश की सुरक्षा व सांस्कृतिक पहचान को बचाने का विषय है. भाजपा इस मुद्दे के सहारे एक तीर से कई निशाने साध रही है. यह विषय सीधे पार्टी के मूल वैचारिक एजेंडे में शामिल राष्ट्रवाद, सैन्य सम्मान और हिंदुत्व से जुड़ा है, साथ ही आइएमए जैसे संवेदनशील सैन्य संस्थान के पास जमीन आवंटन का मुद्दा उठाकर भाजपा इसे देश की सुरक्षा से जोड़ रही है.

दूसरा, यह मुद्दा कांग्रेस को फिर से तुष्टीकरण की राजनीति के कटघरे में खड़ा करने का अवसर दे रहा है. वर्ष 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद को भाजपा ने जिस तरह चुनावी तौर पर भुनाया था, धौलास का यह मामला उसी राजनीतिक पटकथा की अगली कड़ी जैसा दिखता है.

राज्यसभा में बढ़ेगी भाजपा की ताकत

अप्रैल में खाली होंगी सात सीटें, किसे मिलेंगी कितनी सीटें?

मुंबई. लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा था. अब करीब दो साल बीजेपी को महाराष्ट्र से ही राज्यसभा में मजबूती मिलेगी. 2 अप्रैल को महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, फौजिया खान (एसपी), प्रियंका चतुर्वेदी (ठाकरे गुट), रजनी पाटील (कांग्रेस), धैर्यशील पाटील (बीजेपी), भागवत कराड (बीजेपी) और रामदास आठवले (बीजेपी) शामिल हैं. राज्य विधानसभा में मौजूदा संख्या बल

को देखते हुए 7 में से 6 सीटों पर महायुति चुनाव जीतने की स्थिति में है.

एमवीए की स्थिति कमजोर- एक सीट महाविकास आघाडी के खाते में जा सकती है. अप्रैल में राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता का दिल्ली में होना महाराष्ट्र के लिए जरूरी है. बता दें कि महाराष्ट्र से राज्यसभा की कुल 19 सीटें हैं. इनमें 12 सीटें एनडीए के पास हैं, जबकि 7 सीटें महाविकास आघाडी के पास हैं. अप्रैल 2026 के बाद यह आंकड़े बदल जाएंगे.

एक सीट के कितने वोट चाहिए?

जानकारों का कहना है कि विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या के आधार पर 7 सीटों में से बीजेपी को 4, राष्ट्रवादी को 1, शिंदे गुट को 1 सीट मिल सकती है. जबकि महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है.

विशेष क्या योजना के तहत हिंदू मतों को बांटकर भाजपा को हराएगा विपक्ष?

यूपी में सपा-कांग्रेस का प्लॉन बी

लखनऊ. यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल रणनीतिक बिसात बिछाने में लगे हुए हैं. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान खुलकर सामने आई है. भाजपा के राजनीतिक इकोसिस्टम में खींचतान को प्रायोजित बताया जा रहा. एक पूर्व भाजपा विधायक ने दावा किया कि भाजपा को हराने के लिए यह एक बड़े राजनीतिक षडयन्त्र का हिस्सा है.

पूर्व विधायक और बीजेपी नेता बृजेश मिश्र सौरभ ने कहा कि यूपी में सपा-कांग्रेस के पास गठबंधन में भाजपा से लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है. सपा कांग्रेस की सारी उम्मीद इस बात पे टिकी है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा के पक्ष में गोलबंद हिंदुओं के वोट को बांट दिया जाए. पूर्व बीजेपी विधायक ने दावा कि इसी कड़ी के तहत सपा-कांग्रेस की योजना आपस दुश्मनी दिखाकर अलग अलग चुनाव लड़ना है.

एक-दूसरे की मदद के लिए एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ सवर्ण, पिछड़े, दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा जो भाजपा और एनडीए के सामने सपा कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करें. खासकर कांग्रेस सवर्ण चेहरों के जरिए भाजपा को नुकसान पहुंचा कर सपा की मदद करने की योजना में है, ताकि 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के लिए जमीन तैयार की जा सके.

बृजेश मिश्र ने कहा कि बिहार में राजद के साथ कांग्रेस के गठबंधन का कोई लाभ नहीं मिला. यूपी में भी कांग्रेस का कोई विशेष आधार नहीं है तो इस फॉर्मूले पर कांग्रेस, विधानसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए सपा की बड़ी मदद कर सकती है.

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद का नैरेटिव प्रायोजित

चुनाव से पहले हिन्दुत्व की राजनीति से जुड़े मुद्दों को सपा और कांग्रेस की तरफ से हवा दिया गया. इस पर राजनीतिक विश्लेषकों ने हैरानी जताई. बनारस में मणिकर्णिका, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद और ब्राह्मणों की नाराजगी का नैरेटिव विपक्ष की रणनीतिक योजनाओं से जोड़कर देखा गया. अविमुक्तेश्वरानंद के मसले पर अजय राय और अविनाश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस ने खुलकर बैटिंग की और समाजवादी पार्टी अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे खड़ी नजर आई. पूर्व विधायक बृजेश मिश्र सौरभ ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदू समाज भाजपा के पक्ष में एकजुट है.